Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 04-12-2006
Participants : Singh Ch. Lal,Pawar Shri Sharad Chandra Govindrao

an>

Title: Further discussion regarding rise in prices of essential commodities raised by Dr. Chinta Mohan on the 30th November, 2006.

MR. SPEAKER: Now, we shall resume discussion under Rule 193 regarding price rise.

Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' -- Not present

Prof. Ramadass -- Not present.

Now, Chaudhary Lal Singh.[MSOffice8]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि डा. चिन्ता मोहन नियम 193 के तहत आ वश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में डिसकशन लाये हैं.। कहा गया कि जरूरी चीजों के मूल्यों में रेट्स बढ़े हैं। उसके लिये भारत सरकार ने काफी प्रयास किये हैं और काफी कोशिशें भी हुई हैं। मेरा भी यही कहना है कि आज मूल्यों पर कंट्रोल किया जाये।

अध्यक्ष जी, मैं कुछ कमियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस महंगाई का मेन रीज़न रहा कि किसानों को उसके गेहूं का पिछली बार ठीक रेट नहीं दिया गया। सरकार ने गेहूं का रेट 650 रुपये क्विंटल निकाला था। इससे किसानों के साथ बेइन्साफी हुई थी...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Price rise is being discussed. The Minister has to reply. If Members are not prepared to listen to that, let the whole country see what is happening. I cannot do anything.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : सरकार गेहूं के बारे में जो पौलिसी लाई, उसमें किसानों को उसके गन्दमयील्ड का ठीक रेट दिया जाना चाहिये था। मुझे उम्मीद थी कि इस साल किसानों को उसकी पैडी और गन्दम के सोइंग सीजन के लिये मदद मिलती लेकिन वह सरकार नहीं कर पाई। किसानों के लिये बुवाई का सीजन अक्तूबर और नवम्बर में शुरु होता है...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I appeal to all the Members, including the Leaders of various Parties let the House go on. We are discussing the price rise situation. The Minister will reply. From 3 o' clock other important matters will be taken up. There is no question of adjournment.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : अगर सरकार सीज़न में मदद करती तो ऐसा न होता। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि गन्दम का रेट बढ़ाना चाहिये था। इसी कारण से दूसरी कम्पनियां प्रोक्योरमेंट करती रहीं। आजआम आदमी को तकलीफ हो रही है। इसलिये आटा, और दालें सस्ती होनी चाहियें। लोगों को प्रैट्रोल और डीजल से कुछ नहीं लेना है, उसे आटा और दालें सस्ती मिलनी चाहिये। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास पर्चेज़िंग पावर नहीं रही है। मेरा सबमिशन है कि आज आटे का भाव कम से कम 4 रुपये किलो कम होना चाहिये। आप देखेंगे कि गन्दम का रेट 650 रुपये तय किया गया तो आटे का भाव 9-10 रुपये किलो कैसा हो सकता है? जहां तक मैने समझा है कि आज आटा बेचकर व्यापारी मुनाफा कमा रहा है जबकि किसान को उसका मूल्य नहीं दिया गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान को रेट ज्यादा मिले और आम आदमी के लिये आटा और दाल का रेट कम किया जाये। यह बहुत ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार फूड सिक्योरिटी करती है लेकिन राशन स्टोर में सड़ता रहता है। महंगाई का एक कारण यह भी है कि हमने अंत्योदय योजना, बी. पी.एल. योजना, ए.पी.एल. योजना, आंगनवाड़ी और मिड-डे-मील योजना चालू कर रखी है। वहां देखा गया है कि खाना आधा कच्चा और आधा पक्का होता है, खाने लायक नहीं होने से फैंक दिया जाता है। इससे खाने की बेकद्री होती है। ये स्कीम सरकार लाई है लेकिन कामयाब नहीं हो पायी हैं। इससे महज आटा और चावल महंगे हुये हैं। सरकार और कुछ करे या न करे, आटा और चावल सस्ता करे। जितने होर्डर्स और ब्लैकमार्केटियर्स हैं, उनके लिये एक क्वांटिटी रखने के लिये कह सकती है लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा अनलिमिटेड स्टॉक रखा हुआ है।[s9]

जब अनलिमिटेड माल है तो उसको संभालने के लिए और उसको रोकने के लिए वहां छापा मारा जाए। बीजेपी वालों ने इंस्पैक्टर राज हटा दिया। इन्होंने बरबादी की। इनकी वजह से महंगाई हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर खास ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. महादेवराव शिवनकर।

श्रीमती नीता पटैरिया।

...(व्यवधान)

-

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने देश की आम जनता की समस्या है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब मज़दूर हैं, उनकी समस्या है। ...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER: Please allow the Minister to reply. He is giving reply on a very important matter.

... (*Interruptions*)

श्री शरद पवार : इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। ...(व्यवधान)... आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यूपीए की हुकूमत आने के बाद देश का आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है और विकास की दर आठ प्रतिशत के आस-पास आ गई है। मगर साथ-साथ

इनफ्लेशन का रेट 2006-2007 में 6.29 प्रतिशत तक पहुंचा है। इसमें अत्यावश्यक चीजों का लाइसैन्स नहीं है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह हिन्दुस्तान की परंपरा है। ऐसे ही चलने की परंपरा है।

...(व्यवधान)...

श्री शरद पवार : सभी देशवासियों को मालूम है कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गेहूं, पल्सेज़, चीनी आदि प्रोडक्ट्स के दामों पर कुछ समय तक नियंत्रण नहीं रहा। पैट्रोल का उत्पादन करने वाले कई देशों ने जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं, इसका असर भारत जैसे विकासशील देशों पर हुआ है। ...(व्यवधान)... 2003-04 में जिस पैट्रोल की कीमत 25 डालर प्रति बैरल थी, वह 2004-05 में 48.97 डालर प्रति बैरल हो गई। 2005-06 में वह 55.77 डालर प्रति बैरल हो गई और 2006-07 में 17 नवंबर तक 65.24 डालर प्रति बैरल हो गई। 17.11.06 तक 187 प्रतिशत प्राइस पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ गई है, डीज़ल की कीमत में 234 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कैरोसीन की कीमत में 240 प्रतिशत वृद्धि हो गई और एल.पी.जी. की कीमतमें 154 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई।...(व्यवधान)... मगर एक बात मुझे कहनी है कि इतने बड़े पैमाने पर इस वृद्धि होने के बाद इसका बोझ आम जनता के ऊपर कैसे पड़ सकता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। [MSOffice10] ...(व्यवधान)...

इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको ताज्जुब होगा कि पैट्रोल में जो वृद्धि हुई, उसमें 2723 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी सन् 2005-06 में ऑयल कम्पनी ने स्वीकार की है। अप्रैल तथा सितम्बर 2005 में पैट्रोल में जो वृद्धि हुई, उसमें 2808 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ऑयल कम्पनी ने स्वीकार की है। जहां तक डीजल की बात है, सन् 2005-06 में इसमें जो कीमत बढ़ी, इसमें 12,636 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कम्पनी ने ले ली है और अप्रैल से सितम्बर, 2000 तक 15,502 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कम्पनी ने ली है। जहां तक पीडीएस, कैरोसीन का रेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जो थोड़ा-बहुत बदलाव हुआ है, वह सिर्फ कमीशन के बारे में हुआ है, उसमें सरकार ने जिम्मेदारी ली है।

12.46 hrs

(Shri Mohan Singh in the Chair)

जहां तक कैरोसीन की बात है, सन् 2005-06 में भारत सरकार ने 976 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 14,314 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली है। यह 15,360 करोड़ रुपए का बोझ जनता के ऊपर नहीं आएगा, इस पर ध्यान दिया गया है। अप्रैल या सितम्बर, 2006 तक कैरोसिन में जो वृद्धि अंतरराट्रीय मार्केट के आधार पर हुई, उसमें से 483 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 9845 करोड़ रुपए, यानी कुल 10,328 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली है। जहां तक एलपीजी का सवाल है, जहां पिछले साल भारत सरकार ने 1520 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ले ली है और ऑयल कम्पनी ने 10,246 करोड़ रुपए की जिम्मेदीरी ली और टोटल 11,766 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर पड़ सकता था, मगर वह बोझ जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा, इस पर ध्यान दिया गया है। अप्रैल से सितम्बर, 2000 तक भारत सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी की जो इंटरनेशनल मार्केट में वृद्धि हुई, इसमें से 738 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और 5030 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ऑयल इंडस्ट्री ने ली, यानी 5768 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी इन दोनों ने ली, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर नहीं पड़ा और टोटल अमाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 34 हजार करोड़ की जो वृद्धि हुई, उसका बोझ आम जनता के ऊपर नहीं डाला गया। यह जिम्मेदारी भारत सरकार ने और ऑयल कम्पनी ने अपने ऊपर ले ली, जो एक बहुत बड़ा बोझ आम जनता के ऊपर आ सकता था, इससे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मगर यह हम नजरअंदाज नहीं करते कि पैट्रोल और डीजल की जो कीमत होती है, उसका प्रभाव समाज की कई चीजों पर हो सकता है और कई चीजों या ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने से, डीजल बढ़ने से, चाहे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हो या ट्रांसपोर्ट कास्ट हो, इसके ऊपर कुछ न कुछ असर पड़ा, यह मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी जिस आइटम की कीमत ऊपर गई, वह पल्सेज़ की कीमत थी। जहां तक चना दाल है, 24 नवम्बर, 2004 को दिल्ली मार्केट में चने दाल की कीमत 41 रुपए प्रति किलो थी, वह पिछली 24 मई को 30 रुपए प्रति किलो थी और 30-11-06 से यह 42 रुपए प्रति किलो से 41 रुपए हो गई। यह

छोटा-सा डिकलाइन ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। तुअर की जो दाल है, इसमें 24 नवम्बर को दिल्ली मार्केट में 34 रुपए प्रति किलो का रेट था, इसका रेट भी 25 मई को कम हो गया।[rep11]

...(व्यवधान) उसके पहले 35 रुपए थी, उससे अब थोड़ी सी कम हो गई है। ...(व्यवधान) दिल्ली मार्केट में उसकी कीमत 54 रुपए पर के.जी. थी जो 30 नवम्बर, 2006 को 50 रुपए हो गई। ...(व्यवधान) जहां तक मसूर की दाल की बात है, वह 29 रुपए तक पहुंची। उससे पहले 30 रुपए किलो थी। ...(व्यवधान) स्थिति संतोा जनक नहीं है इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 23 सालों में यदि देखें तो वर्ा 201-2002 में 13 प्रतिशत, 2002-03 में 13.5 प्रतिशत और वर्ा 2003-04 में 14.91 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुआ। ...(व्यवधान) जैसा सभी को ज्ञात है कि यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। हम इसे अन्य देशों से इम्पोर्ट करते हैं। जिन देशों से हम ज्यादा इम्पोर्ट करते थे उनमें मियानमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। इन देशों में मौसम खराब होने के कारण उत्पादन कम हुआ और जो हम वहां से इम्पोर्ट करते थे, वह नहीं कर सके। इस साल केवल 20.4 लाख टन ही हम इम्पोर्ट कर सके जिसका असर डॉमैस्टिक मार्केट पर हुआ। ...(व्यवधान) जहां तक एडीबल ऑयल सीड्स की बात है, इसके ज्यादा उत्पादन पर हमें जोर देना पड़ेगा। इनकी कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे रेट बढ़े।

The overall production of pulses during 2005-06 is 13.11 million tonnes, which is lower than the production of 13.13 million tonnes in 2004-05 and 14.91 million tonnes in 2003-04. … (*Interruptions*)

Among pulses, there is a substitutability excepting for urad, and as a result, increase in price of one variety of the pulses leads to shift in the demand to other varieties and consequently results in an increase in the prices of different varieties of pulses. … (*Interruptions*)

Pulses are grown mainly on marginal and sub-marginal land under rainfed conditions with low input usage. The percentage of area under irrigated conditions is only 15 per cent, exposing these crops to weather related yield risks. Consequently, pulses production in India is characterized by fluctuating production and low yield. … (*Interruptions*)

Despite concerted efforts, no major breakthrough in pulses production technology and improvement of high-yielding germ plasm has been possible because of inherent genetic problems and narrow adaptability in the evolved varieties of pulses. … (*Interruptions*)

There is also inadequate seed availability with a seed replacement rate of only 2 per cent - 5 per cent.

Consumption of pulses *per capita* has been increasing in the country. The gap between demand and supply is met through import of 1.5-2.0 million tonnes per annum. This year the crop in Pakistan and Bangladesh has also been adversely affected leading to significant rise in international prices of *urad* and *chana* which is mainly imported from Myanmar (Import of pulses during 2005-06 was 16.08 lakh tonnes. In 2006-07 up to August, 2006 it is only 5.89 lakh tonnes).

The pulses are genetically low yielding and less input responsive as compared to cereals and oilseeds. … (*Interruptions*)

The area under cultivation of pulses has fluctuated between 20 and 24 million hectares in the last ten years. This clearly demonstrates that the cultivation of pulses is not a preferred choice of

farmers, if other alternatives are available. … (*Interruptions*)

Inadequate attention is given to enhancement of irrigation (even life saving irrigation) for land under cultivation of pulses. Since there is no significant improvement in irrigation, there is unlikely to be a significant increase in productivity. This needs to be compared with States like Gujarat where productivity of groundnut (oilseed) and cotton (commercial crop) has gone up significantly with an increase in irrigation. … (*Interruptions*)

The productivity of pulses has remained stagnant between 550 and 600 kgs per hectare for more than a decade. There are yield gaps within the States and between the States. … (*Interruptions*)

Pulses are more prone to pest and diseases. The Integrated Pest Management Practices for pulses have not been given the required attention as the farmers growing pulses as main crops, are resource poor.

Now, I come to steps taken to check rise in prices of Pulses. The Government isaware of the increase in prices of essential commodities such as pulses and has responded by taking a series of measures. The important measures taken are given below:-

1. Customs duty on import of pulses was reduced to zero on June 8, 2006 and a ban was imposed on export of pulses with effect from June 27, 2006.

2. At the initiative of the Government, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) executed a contract for import of 49,300 MTs of pulses, of which 48,061 MT, comprising 35,168 MT or Urad and 12,893 MT of Moong have been shipped as on 21.11.2006. Steps were taken by other agencies. … (*Interruptions*)

3. Reintroduction of enabling provisions to prescribe stock limits and licensing requirements (in August 2006) under the EC Act for the State Governments.

4. Importing of 5.89 lakh tonnes of pulses till August 2006 in 2006-07. … (*Interruptions*) चीनी की परिस्थिति यह थी कि चीनी का …(व्यवधान) इसमें इसलिए सुधार की स्थिति हमें देखने को मिली। जहां तक गेहूं की स्थिति है इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। इसके प्रक्योरमेंट में थोड़ी समस्या आई है। हम कई प्रदेश सरकारों के सहयोगन न किए जाने के कारण 9 मिलियन प्रक्योरमेंट नहीं कर सके और सिर्फ 5.5 मिलियन टन ही प्रक्योर कर सके। …(व्यवधान) यह स्थिति बड़ी गम्भीर है। एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट के आधार पर कई कदम उठाए जाने की कोशिश की है।…(व्यवधान) [r12] पिछले साल का गेहूं का पुराना अनुभव हमारे सामने आ रहा है।…(व्यवधान)इस साल 15 प्रतिशत से ज्यादा सोइंग ऑपरेशन पूरे देश में हुआ है, जमीन में मोएस्चर अच्छा है और मुझे विश्वास है कि पैडी और व्हीट का उत्पादन इस देश में बढ़ेगा और खाद्य समस्या में इससे कुछ न कुछ राहत मिलेगी। …(व्यवधान)

यह जो स्थिति है, यह स्थिति ऐसे समय पर पैदा हुई, जब हमारे यहां उत्पादन कम हुआ, लेकिन इसमें कोई रास्ता निकालने के लिए इस सरकार की हमेशा कोशिश है और कोशिश रहेगी।…(व्यवधान)मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करके हम किस तरह से अनाज की समस्या हल कर सकते हैं, इस पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा और इस सरकार की इसके ऊपर प्रायोरिटी रहेगी।…(व्यवधान)आम जनता को इससे जो यातना होती है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। …(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को काफी भूख लग गई है, इसलिए खाना खाने के लिए हम दो बजे तक उठते हैं।

12.55 hrs

The Lok Sabha then adjourned till

Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at three minutes past

Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) :उपाध्यक्षमहोदय,आज सुबह जो कुछ हाउस में हुआ, हम एक …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have allowed him. Please listen.

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, सिंगूर में किसानों पर जो अत्याचार हुआ और हमारे राट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, हम इस बात को सदन में उठाना चाहते थे। हम वेल में नहीं आना चाहते थे, परंतु आज हमें बोलने नहीं दिया गया। यूपीए की सरकार, कांग्रेस पार्टी …(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, you have to allow us. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, how can he question the Chair? … (*Interruptions*)[v13]

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, nothing has happened… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह सरकार ऑपोजीशनका गला दबाना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है। आज जब हाउस आर्डर में नहीं था …(व्यवधान) इन्होंने हाउस आर्डर में न होने के बावजूद यहां …(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, under what rule are you allowing him to speak… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have allowed him. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, they cannot raise the issue like this… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: First of all, you go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Except Shri Malhotra's submission, nothing else will go on record.

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गोली चली, वहिशयाना लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ। … (व्यवधान) हमें यहां इस बात को उठाने नहीं दिया। अगर कल कहीं श्रीमती सोनिया गांधी गिरफ्तार हो जाएं, तो इनका रवैया कैसा होगा? …(व्यवधान) जैसे हरियाणा में हुआ था। …(व्यवधान) यहां हाउस को एडजर्न कर दिया गया। …(व्यवधान) आज इन्होंने जैसा किया है, उसके खिलाफ हम प्रोटैस्ट करना चाहते हैं। यदि सरकार यह चाहती है कि ऑपोजीशन सदन की कार्यवाही में भाग न ले, तो आज हम कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते। हम इनको खुली छूट देते हैं कि यह ऑपोजीशन को बुलडोज करें, थ्रैश करें और जो बहस करना चाहते हैं, करें। हम आज सारे दिन के लिए हाउस का बहिकार करते हैं।

14.06 hrs

(Then Shri Vijay Kumar Malhotra and some

other Hon'ble Members left the House)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have allowed him to speak. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, इस बिल के बाद आपका ही आइटम है।

…(व्यवधान)